percentage in total plan and its position compared to private sector;

(b) what is the capital investment envisaged in private sector i.e. small, middle and big; and

(c) what is the projected impact on employment in the Eighth Five Year Plan period, what is the expected backlog at the commencement of the Plan and at the end of the Eighth Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

संसद सदस्यों द्वारा पासपोर्ट के आवेदन पत्रों के सत्यापन

*15. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले संसद सदस्यों को पासपोर्ट फार्म तसदीक करने का अधिकार था और अब पिछले कई वर्षों से उन्हें यह अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इससे जनता को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क)जी हां

(ख) दिसम्बर, 1984 में तब के सुरक्षा वातावरण को देखते हुए यह फैसला किया गया था कि पुलिस और सी० आई० डी० सत्यापनों के बिना पासपोर्ट जारी न किए जाएं ।

(ग) जी हां ।

Measure for the Welfare of Indians in Libya

*16. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of Indian Nationals in Libya at present; and

(b) what measures have been taken for their welfare in view of the recent UN sanctions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The number of Indian nationals in Libya is estimated to be between 13,000 to 15,000.

(b) In consultation with the Indian Embassy in Tripuli, measures have been devised to minimise the hardship to Indian nationals in the event of any emergency arising from the imposition of the UN sanctions.

चकमा शरणार्थियों पर व्यय

*17. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री धूलेश्वर मीणा :

क्या **विदेश** मंत्री 30 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4402 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के रोहिंग-मुसलमानों को चटगांव के पर्वतीय क्षत्रों में बसाने की बंगलादेश सरकार की कथित योजना के कारण त्रिपुरा में कुछ हजार चकमा शरणार्थियों को स्वदेश भेजने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न शिविरों में इस समय कुल कितने चकमा शरणार्थी ठहरे हुए हैं और 1991–92 के वर्ष के दौरान उनके भरण-पोषण पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एड्ओर्डो फेलेरियो) : (क) बंगलादेश की सरकार म्यांमार के सभी शरणार्थियों को चटगांव पहाड़ी क्षत्रों में बसाने की बजाय उन्हे उस देश में वापस भेजने पर जोर दे रही है। जब तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक चकमा शरणार्थियों को बंगलादेश वापस भेजने की हमारी व्यवस्था पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) इस समय त्रिपुरा के शिविरों में लगभग 53,200 चकमा शरणार्थी हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1991–92 के दौरान उनकी देखभाल के लिए त्रिपुरा सरकार को 838 लाख रुपये दिये थे ।

न्यायधीशों की संख्या का बढ़ाया जाना

*18. **श्री राम अवतेश सिंह**: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री 9 मार्च, 1992 और 23 मार्च, 1992 को राज्य सभा में क्रमशः अतारांकित प्रश्न सं० 1676 और 3282 के दिए गए उत्तरों को देखेंग और यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में प्रतिवर्ष कितने नए मामले दायर किए जाते हैं और कितने मामले निपटाए जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 50 करने और राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालयों की संख्या को दुगुना करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) पिछले तीन वर्षों की जानकारी निम्नलिखित है :–

वर्ष	संस्थित मामले	निपटाए गए मामले
1989	52138	48118
1990	38293	56343
1991	42215	93102

(ख) जी नहीं।

Model Scheme for Workers' Cooperatives

*19. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether in view of the growing incidents of failure of public sector and private sector units Government have thought of or prepared a model scheme or outlines for third sector, workers' co-operative sector; if so, what are the details thereof if not, what are the reasons therefor; and

(b) whether Government have worked out any solution in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) No, Sir. However, revival of a sick industrial company through workers' co-operatives is one of the measures envisaged under the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. This is one of the options that is considered by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) when considering rehabilitation of sick units. Now, the sick public sector units have also been brought under the purview of BIFR.